youtube.com/dhurandhar times
twitter.com/dhurandhar times
facebook.com/DHURANDHAR TIMES

www.dhurandhartimes.com 9015441661, 8700925835 मूल्य: ₹ 2/- संपादक- धुरन्धर चौहान

धुरन्धर टाइम्स

परिवर्तन की ओर...

वर्ष : 8, अंक : 6, नई दिल्ली, दिसंबर 2023

dhurandhartimes@gmail.com मासिक RNI : DELHIN/2016/71837 दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी मासिक समाचार पत्र

तब जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल : आतिशी

हवन और भंडारे के साथ सात दिवसीय भागवत कथा सम्पन्न

बिहार खुर्द के पंचायत भवन में सात दिवसीय भागवत कथा सम्पन्न

संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

समउर बाजार। बिहार खुर्द (बंगला टोला) पंचायत भवन के प्रांगण में सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत आत्म कथा महायज्ञ का आयोजन ग्राम विकास समिति बिहार खुर्द की तरफ से किया गया। जिसमें धर्मनगरी वृन्दावन धाम से पधारे कथा वाचक पंडित आचार्य संतोष भारद्वाज जी महाराज और आचार्य मनीष भारद्वाज सहित आचार्य प्रिंस मिश्रा द्वारा मन्त्रोंचारण सहित हवन पूजन किया गया। सभी भक्तगण इस हवन पूणार्हुति में अपनी-अपनी आहुति डालकर गांव और क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि के लिए मंगलकामना किया।

कथावाचक पंडित श्री संतोष भारद्वाज जी, आचार्य मनीष भारद्वाज, आचार्य प्रिंस मिश्रा सहित वृन्दावन धाम से पधारे गायक कलाकारों का सॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। ऊँचे स्वर में समस्त देवी-देवताओं का जय-जयकार किया गया। वेद मन्त्रोंचारण के साथ इस सात दिवसीय श्रीमदभागवत आत्म कथा महायज्ञ सम्पन्न हुआ। हवन के दौरान श्री दुर्गा माता मंदिर स्थित यज्ञशाला में शिवसरयां नकहा मंदिर से श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, महंथ श्री कुण्डल बाबा जी, हनुमान मंदिर भागीपट्टी श्री हनुमान मंदिर के पुजारी श्री लोकेश दास जी, श्री गोपाल गुप्ता(पूर्व ग्राम प्रधान), प्रिंस खरवार(बी.डी.सी.), प्रभु आनंद मद्धेशिया, मिथलेश मद्धेशिया, रितेश मिश्रा, रविन्द्र शर्मा, सुमित खरवार, रोहित, टोनी खरवार, दीपेश, श्यामप्रताप राव, कृष्णा, अलोक पाल, असरम चौहान, राकेश चौहान, श्रीराम खरवार, जीतू, गायक और अभिनेता धर्मेंद्र खरवार, अभय यादव, वीरेंद्र पाल, योगेश शर्मा, श्रीकांत प्रजापति, हंसराज खरवार, भूद्धू राव, संजय शर्मा, धुरन्धर चौहान, चौहान, के अलावा सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। हवन-पूजन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

भगवान का अवतार धरती पर विशेष प्रयोजन के लिए होता है -पंडित संतोष भारद्वाज

संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

समउर बाजार। बिहार खुर्द (बंगला टोला) पंचायत भवन के प्रांगण में सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत आत्म कथा का आयोजन ग्राम विकास समिति बिहार खुर्द बंगला टोला की तरफ से किया गया है। जिसमें धर्मनगरी वृन्दावन धाम से पधारे कथा वाचक पंडित आचार्य संतोष भारद्वाज जी महाराज ने कथा के पांचवे दिन भक्त समुदाय को सम्बोधित करते हुए वृन्दावन धाम से पधारे पंडित आचार्य संतोष भारद्वाज जी महाराज ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भगवान का अवतार धरती पर विशेष प्रयोजन के लिए होता है। जब धरती पर आसुरी प्रवृति वालों का बोल बाला बढ़ जाता है, तब भगवान भक्तों और सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान शरीर धारण कर साकार रूप में आते है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता श्री संदीप तिवारी ने फीता काटकर आज के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया और कथावाचक पंडित बाल व्यास संतोष भारद्वाज जी महाराज को तिलक और पुष्पहार सहित मंचासीन गायक कलाकारों का भी पटके द्वारा सम्मानित किया। कथा व्यास संतोष भारद्वाज ने पटके पहनाकर मुख्य अतिथि को आशीर्वाद दिया। गायक कलाकारों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाईयाँ गाकर सभी भक्तों को खूब नचाया। पांडाल में उपस्थित भक्तों ने मिठाईया बांटकर और नाच गाकर धूमधाम से जन्मोत्सव का आनंद लिया।प्रवचन के दौरान पांडाल में श्रीकांत प्रजापति, हंसराज खरवार, भूद्धू राव, संजय शर्मा, रविन्द्र शर्मा, धुरन्धर चौहान, प्रिंस खरवार के अलावा सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। आरती-पूजन के साथ सायंकालीन कथा को विश्राम किया गया।

बिहारखुर्द, कुशीनगर श्रीमदभागवत आत्मकथा महायज्ञ में प्रात:कालीन हवन-पूजन करते भक्तगण और यजमाने

भक्त ध्रुव जैसा हमारा भी दृढ़ निश्चय और विश्वास हो तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे : पंडित संतोष भारद्वाज

संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

समउर बाजार। बिहार खुर्द (बंगला टोला) पंचायत भवन के प्रांगण में सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत आत्म कथा का आयोजन ग्राम विकास समिति बिहार खुर्द बंगला टोला की तरफ से किया गया है। जिसमें धर्मनगरी वृन्दावन धाम से पधारे कथा वाचक पंडित आचार्य संतोष भारद्वाज जी महाराज ने भक्त समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भक्त ध्रुव जैसा हमारा भी दृढ़ निश्चय और विश्वास हो तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे

प्रतिदिन की भांति आज भी प्रातः 7 बजे से बंगला टोला के श्री दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में निर्मित यज्ञशाला में पूजन और हवन का कार्य परीक्षित श्री ललन चौहान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी और यजमान श्री अदालत चौहान और पत्नी मंदोदरी देवी से यज्ञाचार्य पंडित मनीष भारद्वाज जी वृन्दावन से और पंडित प्रिंस मिश्रा जी (बनारस) ने विधि-विधान से मन्त्रोंच्चारण द्वारा हवन-पूजन संपन्न कराया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ.विजय कुमार राय (पूर्व ब्लॉक प्रमुख तमकुहीराज व वरिष्ठ भाजपा नेता)ने फीता काटकर आज के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया और कथावाचक पंडित बाल व्यास संतोष भारद्वाज जी महाराज को मुकुट और पुष्पहार पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। कथा व्यास संतोष भारद्वाज ने पटके पहनाकर मुख्य अतिथि को आशीर्वाद दिया। दिल्ली से आये हुए प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार अमर रंगीला उर्फ अमर दास और उनकी टीम ने अपने सुमधुर भजनों पर सबको नाचने पर मजबूर कर दिया।

प्रवचन के दौरान पांडाल में सागर खरवार, घनश्याम खरवार, आनंद, विशाल, नागेश्वर खरवार, विनय खरवार, नंदन कुशवाहा, राधे गुप्ता, रामप्रीत राव, सुनील सिंह, धुरन्धर चौहान, प्रिंस खरवार के अलावा कथा श्रोता सैकड़ों पुरुष और महिलाएं उपस्थित थे। आरती-पूजन के साथ सायंकालीन कथा के दूसरे दिन को विश्राम किया गया।

भव्य कलश यात्रा के साथ सात दिवसीय श्रीमद्भागवत आत्म कथा महायज्ञ प्रारम्भ

संवाददाता, धुरंधर टाइम्स कुशीनगर।

ग्राम विकास समिति बिहार खुर्द (बंगला) पंचायत भवन में 7 दिवसिय संगीतमय श्रीमद् भागवत आत्म कथा महायज्ञ का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया है। बिहार खुर्द के श्री दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण से प्रातः 9 बजे से भव्य कलश यात्रा के साथ सात दिवसीय श्रीमद्भागवत आत्म कथा महायज्ञ प्रारम्भ किया गयो कुशीनगर जिला के प्रभारी महात्मा अनुरागानंद जी और तमकुहीराज ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ वशिष्ठ कुमार राय(गुड्डू राय) ने भगवा झंडी दिखा कर यात्रा का शुभारम्भ किया

यात्रा बिहार बुजुर्ग, कटहरी बाग, रगड़गंज, शिव सरया, तमकुहीराज से होते हुए प्रसिद्ध स्थल शिवा घाट पर सैकड़ों वाहनों द्वारा पंहुचो घाट पर वृन्दावन धाम से पधारे आचार्य मनीष भारद्वाज और आचार्य प्रिंस मिश्रा ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया और कलश में जल भरने के उपरांत तमकुहीराज, पिपरा बघेल होते हुए समउर बाजार पहुंचे जहाँ वाहनों से उतर कर समस्त भक्तगण और सैकड़ों की संख्या में सिर पर कलश से सुशोभित माताओं-बहनों ने पुरे समउर बाजार से होते हुए कथा स्थल बिहार खुर्द पंचायत भवन के प्रांगण में यात्रा का समापन किया गयो यह कलश यात्रा कुछ समय बाद कथा के रूप में परिवर्तित हो गयो

कथा के प्रथम दिन वृन्दावन धाम से पधारे कथा वाचक पंडित बाल व्यास संतोष भारद्वाज जी महाराज ने जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि कथा केवल सुनने का विषय नही है

अपितु इसे जीवन में धारण करना पड़ता है,अमल करना पड़ता है।जिस प्रकार औषधि खाने के उपरांत ही उसके गुण अवगुण का पता चलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति जीवन में प्रेक्टिकल करना पड़ेगा तभी इसका लाभ प्राप्त होगा।हम सभी केवल भगवान को मानते है लेकिन महापुरुषों की बातों को नहीं मानते है।

कथा के आरंभ में प्रसिद्ध समाजसेवी और आध्यात्मिक गुरु श्री सतपाल जी महाराज के अनुयायी और कुशीनगर जिला के प्रभारी महात्मा अनुरागानंद जी ने अपने विचारों से कथा में सैकड़ों भक्तों को लाभान्वित किया। कथा में परीक्षित ललन चौहान और धर्मपत्नी राबड़ी देवी और मुख्य यजमान व्यास खरवार ने व्यास मंच पर आसीन पूज्य व्यास जी सहित सभी गायक कलाकारों का फूल-मालाओं और पटके द्वारा स्वागत किया ग्रामप्रधान आलोक(दीपक) सिंह, प्रिंस खरवार (बिडिसी), श्रीराम खरवार, गम्हा मास्टर राव, अनिरुद्ध सिंह, संजय शर्मा, कपिलदेव आदि मौजूद थे।

संपादकीय

सुरंग निर्माण चुनौतियों के बीच जिंदगानी

इन दिनों भारत के पांच राज्यों में चल रहे चुनावी अभियान के बीच जिस खबर ने आम जनता और विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रखा था, वह उत्तराखंड के ब्रह्मखाल-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ों का सीना चीरकर सिलक्यारा और डंडालगांव के बीच लगभग पांच किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य और सुरंग हादसे की घटना की थी जिसमें निमार्णाधीन टनल का एक हिस्सा ढहने के चलते पिछले 12 नवंबर से 41 मजदूरों की बहुमूल्य जिंदगियां दांव पर लगी हुई थीं। आखिरकार मंगलवार देर शाम को वह मंगल खबर आ ही गई जिसका पूरा राष्ट्र एवं सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिवारजन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस दुर्घटना के तुरंत बाद केंद्र सरकार के आग्रह पर अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स भी सिलक्यारा पहुंच गए थे और उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ चर्चा करके आगामी रणनीति तैयार की थी कि किस प्रकार से सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अन्य एजेंसियों के अधिकारी और इंजीनियर भी अपने-अपने हिसाब से बचाव अभियान में जुटे रहे। सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान में पिछले सोमवार को एक महत्त्वपूर्ण कामयाबी तब मिली थी जब बचाव कर्मियों ने सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में ड्रिलिंग कर मलबे के आरपार 53 मीटर लंबी छह इंच व्यास की पाइपलाइन डाल दी थी जिसके जरिये सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों तक पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, संचार उपकरण तथा अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाना संभव हो पाया। दूसरी ह्यलाइफ लाइनह्न कही जा रही इस पाइपलाइन के जरिए जब श्रमिकों तक ताजी रोटी और सब्जी भेजी गई तो पिछले 9 दिनों से ड्राईफ्रूट और बिस्कुटों पर निर्भर श्रमिकों को राहत मिली। एक वक्त सिलक्यारा सुरंग के भीतर राह बनाने की जुगत में लगी ऑगर मशीन के फिर से अटक जाने के कारण श्रमिकों के लंबे समय तक फंसने की आशंका बढ़ गई थी और जब अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स से इस संबंध में समय सीमा बताने के लिए कहा गया तो उनका कहना था कि श्रमिक क्रिसमस तक घर आ पाएंगे। लेकिन विशेषज्ञों के अनुमानों के विपरीत रैट माइनर्स ने असंभव से लग रहे कार्य को महज दो दिनों के अथक परिश्रम से सार्थक बनाकर सुरंग के दूसरे छोर में फंसे श्रमिकों तक पहुंच बनाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।सिलक्यारा की दुर्घटना के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हिमाचल में नेशनल हाईवे को फोरलेन में बदलने के बीच बन रही टनल में कंपनियों को सुरंगों के भीतर पहले से ही सुरक्षा उपायों को लागू करने के आदेश जारी किए थे। इसके लिए टनल निर्माण वाली जगहों का औचक निरीक्षण भी नियमित रूप से किया जाएगा। इस दौरान बुनियादी ढांचे के साथ ही निर्माण की जानकारी भी जुटाई जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल में बारिश की तबाही से सडकों को बचाने के लिए एनएच के अधिकतर हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सुरंगें बनाने का फैसला लिया गया है और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए नए प्रारूप तैयार किए जा रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग और चार धाम जैसी परियोजनाओं के लिए आम तौर पर पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन (ईआईए) करने की आवश्यकता होती है। सूचना के मुताबिक इस परियोजना के लिए ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया। पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने संबंधी जरूरतों को दरकिनार करते हुए इस परियोजना को 100 किलोमीटर से छोटे कई खंडों में विभाजित किया गया था। अब इस दुर्घटना से सबक लेते हुए हिमाचल में प्रस्तावित सभी टनल्स के बाहर ड्रिलिंग मशीनें रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई हादसा होता है तो बिना समय गंवाए ड्रिलिंग शुरू हो सके। इसके साथ ही सुरंग निर्माण से पहले मिट्टी के सैंपल की भी जांच होगी ताकि हादसे की संभावना को टनल में दाखिल होने से पहले ही खत्म किया जा सके।

(चिंतन-मनन)

विनम्रता का पाठ

पंडित विद्याभूषण बहुत बड़े विद्वान थे। दूर-दूर तक उनकी चर्चा होती थी। उनके पड़ोस में एक अशिक्षित व्यक्ति रहते थे-रामसेवक। वे अत्यंत सज्जन थे और लोगों की खूब मदद किया करते थे। पंडित जी रामसेवक को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उनसे दूर ही रहते थे। एक दिन पंडित जी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी एक राहगीर उधर आया और मोहल्ले के एक दुकानदार से पूछने लगा-भाई यह बताओ कि पंडित विद्याभूषण जी का मकान कौन सा है। यह सुनकर पंडित जी की उत्सुकता बढ़ी। वह सोचने लगे कि आखिर यह कौन है जो उनके घर का पता पूछ रहा है। तभी दुकानदार ने उस राहगीर से कहा-मुझे तो किसी पंडित जी के बारे में नहीं मालूम। तब राहगीर ने कहा-क्या रामसेवक जी का घर जानते हो?

दुकानदार ने हंसकर कहा-अरे भाई उन्हें कौन नहीं जानता। वे बड़े भले आदमी हैं। फिर उसने हाथ दिखाकर कहा- वो रहा रामसेवक जी का घर। फिर दुकानदार ने राहगीर से सवाल किया-लेकिन आपको काम किससे है? पंडित जी से या रामसेवक जी से? राहगीर कहने लगा-भाई काम तो मुझे रामसेवक जी से है।

राजस्थानी राजनीति के अपरिहार्य चेहरे हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे

-उमेश चतुर्वेदी-

संसदीय लोकतंत्र में सत्ता की कमान जिन्हें मिलती है, उनका सबसे बड़ा आधार राजनीतिक दल हैं। दिलचस्प यह है कि जिस लोकप्रतिनिधित्व कानून के जरिए देश में चुनाव होते हैं, उनमें राजनीतिक दल का जिक्र तो है, लेकिन राजनीतिक दलों की बात संविधान में कहीं नहीं है। संसदीय राजनीति के केंद्र बिंदु बने राजनीतिक दलों के लिए तय है कि उनमें अंदरूनी लोकतंत्र रहे और चुनाव होते रहें। लेकिन देश के तकरीबन सभी दलों में अंदरूनी लोकतंत्र की सिर्फ रस्म निभाई जाती है। अव्वल तो हर दल में अपना-अपना शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व उभर चुका है। केंद्रीय नेतृत्व की ही मर्जी पर राज्यों के क्षत्रपों का नाम राजनीतिक दल तय करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की आंख से उतरा नहीं कि स्थानीय नेतृत्व किनारा हो जाता है। लेकिन अपने देश में एक राज्य ऐसा भी है, जहां इस परिपाटी को चुनौती मिल रही है। इस राज्य में प्रमुख रूप से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा है। लेकिन दोनों ही दलों के पास इस राज्य में एक ऐसा स्थानीय नेतृत्व है, जो अपने-अपने दलों के शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व को परोक्ष रूप से चुनौती दे रहा है। अव्वल तो दूसरा कोई होता तो दोनों ही दल अपने इन नेताओं को किनारे लगा चुके होते। लेकनि इनकी स्थानीय स्तर पर ताकत ऐसी है कि मौजूदा विधानसभा चुनावों में दोनों ही दलों को अपने स्थानीय ताकतवर नेतृत्व को नकार पाना संभव नहीं रहा। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर वह कौन-सा राज्य है, जहां दोनों दलों में ऐसा स्थानीय नेतृत्व है, जिसे अपने केंद्रीय नेतृत्व की परवाह नहीं है। कुछ लोग अनुमान लगा भी रहे हैं। जी हां, आपने ठीक फरमाया, वह राज्य राजस्थान है। और यहां के दोनों दलों के स्थानीय क्षत्रप इतने ताकतवर हैं कि उनके बिना दोनों ही दल अपनी स्थानीय राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ हैं कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ हैं भाजपा की नेता और दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे सिंधिया। दोनों नेताओं की अपने-अपने समर्थक आधार पर पकड़ ही है कि दोनों ही दल अपने इन नेताओं को नकारने की हिम्मत नहीं दिखा सके। अशोक गहलोत से उनके पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सुपर आलाकमान राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें दिल्ली से लेकर जयपुर तक के सियासी वायुमंडल में फैली हुई हैं। राजस्थान के चुनाव प्रचार में इसका असर दिखा भी। राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद राहुल गांधी महज चार घंटे के लिए राजस्थान पहुंचे और तीन जनसभाओं को संबोधित किया। राजस्थान में विधानसभा की दो सौ सीटें हैं, लेकिन राहुल गांधी की तीन जनसभाओं के केंद्र में महज डेढ़ दर्जन ही विधानसभा सीटें रहीं। जिन्हें पता है कि कांग्रेस के सुपर आलाकमान इंदिरा परिवार की क्या ताकत होती है, वे जानते हैं कि अगर गहलोत की ताकत नहीं होती तो अब तक उन्हें आलाकमान घुटनों के बल ला चुका होता। लेकिन आलाकमान ऐसा नहीं कर पा रहा है। याद कीजिए, सचिन पायलट के विद्रोह को। उनके विद्रोह के वक्त कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि अशोक इस्तीफा दें। आलाकमान का संदेश लेकर कांग्रेस के दो दूत मल्लिकार्जुन खरगे और अजय माकन जयपुर पहुंचे, लेकिन गहलोत ने ना सिर्फ इससे इनकार कर दिया, बल्कि शांति धारीवाल की अगुआई में विधायकों ने अशोक नहीं तो कोई नहीं जैसा समानांतर बगावत कर दी। अशोक गहलोत नहीं माने और अपने दम पर सचिन पायलट का विद्रोह थामने में कामयाब रहे।

उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनकी जगह पर वे खड़गे अध्यक्ष बनाए गए, जो कभी उनके खिलाफ हुई बगावत को थामने के लिए आलाकमान के दूत बनकर जयपुर पहुंचे थे। कांग्रेस आलाकमान शांति धारीवाल को टिकट नहीं देना चाहता था, लेकिन गहलोत उन्हें टिकट दिलाने में कामयाब रहे। आलाकमान रोक नहीं पाया। जिन्हें सोनिया गांधी की राजनीति पता है, उन्हें पता है कि अपने विरोधियों को वे माफ नहीं करतीं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस दौर में एक घोटाले को लेकर संसद में केरल के नेता केपी उन्नीकृष्णन ने सवाल उठाया था। उस दौर में उनके नाम से मिलते-जुलते नाम वाले एक और नेता थे, पी उपेंद्र। पी उपेंद्र बाद में वीपी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बने। उपेंद्र तेलुगू देशम के सांसद थे। सोनिया घोटाला उठाने को लेकर केपी उन्नीकृष्णन से खफा थीं, लेकिन वह उपेंद्र और उन्नीकृष्णन में फर्क नहीं कर पाईं। आंध्र के एक दौरे से पति राजीव के साथ लौटते वक्त उन्हें उपेंद्र दिख गए और उन्हें उन्होंने सार्वजनिक रूप से हड़का दिया था। शांति धारीवाल ने बगावत के दिनों में प्रेस से यहां तक कह दिया था कि कौन हैं सोनिया गांधी। माना जा रहा था कि शांति धारीवाल के राजनीति के दिन लद गए, लेकिन अपने इस वफादार को अशोक

गहलोत टिकट दिलाने में कामयाब रहे या दूसरे शब्दों में कहें तो टिकट उन्होंने दिया, यह जानते हुए भी उनका सुपर आलाकमान उनसे नाराज है।

अब बात करते हैं वसुंधरा की। राजस्थान में वसुंधरा खुद को बीजेपी की सर्वोच्च नेता मानती रही हैं। वे सिर्फ अटल और आडवाणी के सामने झुकती रही हैं। अन्यथा वे किसी के सामने नहीं झुकतीं। याद कीजिए 16 मई 2014 की तारीख को, जब भाजपा इतिहास बनाने जा रही थी। पहली बार केंद्र में अपने दम पर सरकार बना रही भाजपा की क्षत्रप वसुंधरा नाराज होकर राजस्थान की सभी 25 सीटों से जीते भाजपा सांसदों को लेकर दिल्ली के राजस्थान हाउस चली गई थीं। इसके पहले केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बावजूद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था।

राजस्थान में इस बार माना जा रहा था कि वसुंधरा पहले की तुलना में कमजोर हुई हैं, इसलिए वे अपनी उपेक्षा से बगावत कर सकती हैं। लेकिन वसुंधरा ने खुलकर तेवर नहीं दिखाए। लेकिन पर्दे के पीछे वे सक्रिय रहीं। राजस्थान में कहा जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि अगर वसुंधरा को नहीं साधा गया और वे कुछ ऐसा-वैसा कदम उठा लेंगी तो राजस्थान में उसकी सत्ता की उम्मीदें धूमिल पड़ जाएंगीं। इसलिए उन्हें मनाने की कोशिशें पर्दे के पीछे से चलीं। वसुंधरा ने तेवर नहीं दिखाए। कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें राजस्थान के लिए अपरिहार्य मानने को मजबूर हुई।

मोदी का मकसद, कांग्रेस चुनौती न बने!

-अजीत द्विवेदी-

भाजपा ने क्यों पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में इतनी ताकत झोंकी? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को इस तरह दांव पर लगाया? क्यों मोदी और अमित शाह दोनों ने इन चुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है? क्यों ऐन केन प्रकारेण चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है? आखिर पांच साल पहले भी तो इन राज्यों के चुनाव हुए थे और उनमें भी भाजपा हार गई थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटों के साथ जीती फिर इस बार इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? क्या भाजपा को लग रहा है कि इस बार 2018 और 2019 का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा? क्या भाजपा को लग रहा है कि अगर पिछली बार की तरह इस बार कांग्रेस जीती तो 2024 की तस्वीर बदली हुई होगी? या यह माना जाए कि भाजपा के लिए यह रूटीन का मामला है, मोदी और शाह जिस तरह से सारे चुनाव लड़ते हैं वैसे ही ये चुनाव भी लड़ रहे हैं?चार महीने पहले अगस्त में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा के साथ जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनावों का भाजपा ने आगाज किया उसे देख कर साफ लग रहा है कि यह रूटिन का चुनाव नहीं है। पिछली बार से उलट इस बार भाजपा ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया। पिछली बार भाजपा ने राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी ये तीनों नेता चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन चुनाव उनके चेहरे पर नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। यह सही है कि प्रादेशिक नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी का चेहरा ज्यादा लोकप्रिय है और भाजपा को वोट दिलाने वाला है लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का इस तरह अपनी साख दांव पर लगाना सही रणनीति है?असल में पूर्वोत्तर के मिजोरम को छोड़ कर चार राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का विधानसभा चुनाव भाजपा सिर्फ जीत कर अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस को हरा कर अगले साल के लोकसभा चुनाव में उसको चुनौती बनने से रोकने के लिए लड़ रही है। इन चार में से तीन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। अगर आमने सामने की इस लड़ाई में भाजपा को हरा कर कांग्रेस जीतती है तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे, उनकी सरकार के कामकाज और उनके बनाए नैरेटिव और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और उनके मजबूत नेतृत्व के ऊपर राहुल गांधी के करिश्मे और मोहब्बत की दुकान के उनके नैरेटिव की जीत माना जाएगा। इससे स्वाभाविक रूप से यह मैसेज बनेगा कि भाजपा को कांग्रेस अपने नैरेटिव, नेतृत्व और एजेंडे के दम पर हरा सकती है।सीधे मुकाबले में भाजपा को हरा कर कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में मुख्य चैलेंजर के तौर पर उभरेगी। प्रादेशिक पार्टियां भी मान लेंगी कि कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। यह धारणा बनने के बाद विपक्षी पार्टियां अपने आप उसके ईर्द-गिर्द इकट्ठा होंगी। पार्टियों के स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथ गठबंधन में इकट्ठा होने के साथ साथ पूरे देश के भाजपा विरोधी मतदाता भी उसके पीछे खड़े होंगे। भाजपा विरोधी मतदाताओं की पहली पसंद कांग्रेस बनेगी। वे प्रादेशिक पार्टियां का साथ छोड़ कर भी कांग्रेस के पीछे एकजुट होंगे। इससे हिंदी पट्टी का पूरा चुनावी परिदृश्य बदल जाएगा। अब यह सवाल उठेगा कि पिछली बार भाजपा इन तीनों राज्यों में हार गई थी फिर क्यों नहीं चुनावी परिदृश्य बदला था? इसका पहला कारण यह था कि दो राज्यों- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 15 साल से चल रही थी और लोग उबे हुए थे तो राजस्थान में हर पांच साल में राज बदलने का रिवाज रहा है।दूसरा कारण यह था कि ऐसा कुछ केंद्र सरकार के मामले में नहीं था। लोग नरेंद्र मोदी की सरकार से न नाराज थे और न उबे हुए थे। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मोदी से पहले भी देश के मतदाताओं ने मनमोहन सिंह को दूसरी बार सरकार चलाने का मौका दिया था। यह आम धारणा थी कि किसी भी सरकार के लिए एक कार्यकाल पर्याप्त नहीं होता है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर भरोसा किया था और उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई दर्जनों योजनाओ को पूरा करने के लिए एक कार्यकाल और दिया था। तीसरा कारण यह था कि कांग्रेस बहुत बिखरी हुई और कमजोर थी। लोगों ने भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रचार से प्रभावित होकर ही सही लेकिन 2014 में कांग्रेस को जिस अंदाज में सजा दी थी उससे लोगों का जी नहीं भरा था। इसलिए कांग्रेस को लेकर भाजपा के मन में ज्यादा चिंता नहीं थी।इस बार हालात बदले हैं। 2019 के बाद पांच साल में कांग्रेस ने अपने को संभाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दक्षिण भारत के दलित नेता मल्लिकार्जुन खडगे को अध्यक्ष चुनने के बाद कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हुई है। उसके बाद कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव जीता है। तभी हिंदी पट्टी के तीन राज्यों के अलावा दक्षिण में तेलंगाना के चुनाव को भी भाजपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने को झोंका और सारे दांव आजमाए। दलित समूहों के वर्गीकरण के जरिए आरक्षण के भीतर आरक्षण का वादा हो या बाबर, औरंगजेब के नाम पर वोट मांगना हो या प्रवासी भारतीयों के लिए मंत्रालय बनाने का वादा हो, भाजपा ने चुनावी जंग छेड़ी है। वहां भाजपा किसी तरह से कांग्रेस को रोकने की कोशिश में है, चाहे के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति चुनाव जीत जाए।इसका कारण यह है कि कर्नाटक के बाद अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका कांग्रेस को दो फायदा है। पहला, संसाधनों से सक्षम दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो लोकसभा चुनाव लडने के लिए कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। दूसरे, लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस बिग बैंग के साथ वापसी करेगी। ध्यान रहे कांग्रेस हर बार केंद्र में हारने के बाद दक्षिण से ही वापसी करती रही है। तेलंगाना की जीत कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम होगी क्योंकि कर्नाटक के बाद वह दूसरा राज्य होगा, जहां से यह मैसेज बनेगा कि देश का मुसलमान और दलित कांग्रेस के साथ लौट रहा है। राहुल और प्रियंका के साथ साथ खडगे का नेतृत्व भी मजबूत होगा, जिसका फायदा कांग्रेस को पूरे देश में मिल सकता है। इसलिए वहां भी कांग्रेस को रोकने का प्रयास हो रहा है। पांच राज्यों में 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं अगर इसमें से कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो उसका बड़ा लाउड एंड क्लीयर मैसेज देश भर में जाएगा। अब तक भाजपा यह धारणा बना रही थी कि कांग्रेस से लडना उसके लिए आसान है और मोदी बनाम राहुल का चुनाव तो वह आसानी से जीतेगी लेकिन अब वही भाजपा चाहती है कि किसी तरह से कांग्रेस और राहुल से सीधा मुकाबला न बने।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में डीपफेक एक बड़ी चुनौती...

-डॉ. सत्यवान सौरभ-

डीप फेक का गलत इस्तेमाल हर क्षेत्र में होने लगा है, डीप फेक लोकतंत्र के लिये खतरा है। डीप फेक मतदाता के मन को बदल सकता है। डीपफेक द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ सबसे पहले विश्वास और प्रतिष्ठा का क्षरण करती है। डीपफेक का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सामाजिक अशांति भड़काने के लिए किया जा सकता है। एक बार जब कोई डीपफेक वीडियो वायरल हो जाता है, तो नुकसान को रोकना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग वास्तविक और हेरफेर की गई सामग्री के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। व्यक्तियों और समाज के लिए खतरा अब सिर पर आकर खड़ा हो गया है। डीपफेक का इस्तेमाल साइबर बुलिंग, ब्लैकमेल और यहां तक कि चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके दुरुपयोग से व्यक्तियों और समाज को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत अधिक है। पता लगाने और जिम्मेदार ठहराने में कठिनाई पहले से ज्यादा बढ़ गयी है। डीपफेक का परिष्कार लगातार विकसित हो रहा है, जिससे उनका पता लगाना और उनका पता लगाना कठिन होता जा रहा है। यह कानून प्रवर्तन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक चुनौती है। कानूनी और नैतिक विचार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहें है। डीपफेक के उद्भव ने गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की सीमाओं के संबंध में जटिल कानूनी और नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं...

डीपफेक ऐसे वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके हेरफेर किया जाता है, ताकि यह प्रतीत हो सके कि कोई कुछ ऐसा कह रहा है या कर रहा है जो उन्होंने कभी नहीं किया। यह दूरगामी प्रभावों के साथ एक महत्वपूर्ण तकनीकी खतरे के रूप में उभरा है। कहते हैं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में डेटा ही तेल सामान है, मतलब उसका महत्त्व बहुत ज्यादा है, और बिना डेटा के कोई भी काम होना बहुत कठिन हो गया है। जैसे-जैसे डेटा का उपयोग बढ़ रहा है, उसके शोधन के तरीके भी बढ़ रहे हैं, वहीं ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गयी हैं जो आपके डेटा का इस्तेमाल कर कई प्रकार के हैरतअंगेज कार्य कर सकती है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने तकनीकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला है। गूगल बार्ड जैसे टूल्स आश्चर्जनक जानकारियों का खजाना बन गए हैं, जो रिसर्च,एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी को अलग स्तर पर ले गए हैं, वहीं न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग ने सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों को बदल डाला है।

डीपफेक द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ सबसे पहले विश्वास और प्रतिष्ठा का क्षरण करती है। डीपफेक का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सामाजिक अशांति भड़काने के लिए किया जा सकता है। एक बार जब कोई डीपफेक वीडियो वायरल हो जाता है, तो नुकसान को रोकना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग वास्तविक और हेरफेर की गई सामग्री के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। व्यक्तियों और समाज के लिए खतरा अब सिर पर आकर खड़ा हो गया है। डीपफेक का इस्तेमाल साइबर बुलिंग, ब्लैकमेल और यहां तक कि चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके दुरुपयोग से व्यक्तियों और समाज को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत अधिक है। पता लगाने और जिम्मेदार ठहराने में कठिनाई पहले से ज्यादा बढ़ गयी है। डीपफेक का परिष्कार लगातार विकसित हो रहा है, जिससे उनका पता लगाना और उनका पता लगाना कठिन होता जा रहा है। यह कानून प्रवर्तन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक चुनौती है। कानूनी और नैतिक विचार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहें है। डीपफेक के उद्भव ने गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की सीमाओं के संबंध में जटिल कानूनी और नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

डीप फेक का गलत इस्तेमाल हर क्षेत्र में होने लगा है, लोकतंत्र के लिये खतरा है डीप फेक। डीप फेक लोकतांत्रिक संवाद को बदलने और महत्त्वपूर्ण संस्थानों के प्रति लोगों में अविश्वास फैलाने के साथ ही लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर सकता है। डीप फेक राजनीति और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी नेता का गलत बयान, भड़काऊ बयान का वीडियो बनाकर वायरल किया जा सकता है, जिससे देश में दंगे हो सकते हैं। डीप फेक का प्रयोग चुनावों में जातिगत द्वेष, चुनाव परिणामों की अस्वीकार्यता या अन्य प्रकार की गलत सूचनाओं के लिये किया जा सकता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये बड़ी चुनौती बन सकता है। इस साल की स्टेट ऑफ डीपफेक रिपोर्ट के अनुसार, भारत डीपफेक के मामले में छठा सबसे संवेदनशील देश है। डीप फेक मतदाता के मन को बदल सकता है।अगर आपने चुनाव के दो दिन पहले तक किसी दल या उम्मीदवार के लिए पक्ष या विपक्ष में वोट करने के मन बना रखा है और इसी बीच उस दल के बड़े नेता या किसी उम्मीदवार का कोई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो, या ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो ऐसे में मतदाता उस दल या पार्टी को अपने वोट देने के फैसले को बदल सकता है। बता दें कि ब्रिटेन के पिछले प्रधानमंत्री पद के चुनाव में लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवारों का एक डीप फेक वीडियो सामने आया जिसमें वे एक-दूसरे का समर्थन करते दिखाई दिये, इसी प्रकार भारत में भी 2019 के लोकसभा चुनावों में कुछ राजनेताओं के डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसे बाद में हटा दिया गया।

भारत में डीपफेक के पीड़ितों के लिए कानूनी उपाय देखे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने और 36 घंटों के भीतर डीपफेक सामग्री को हटाने के लिए बाध्य हैं। साइबर अपराध की शिकायत करने के लिए पीड़ित राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और साइबर वकील से सहायता ले सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 जालसाजी और झूठी सूचना के प्रसार सहित साइबर अपराध अपराधों से संबंधित है। कॉपीराइट अधिनियम, १९५७ के तहत यदि डीपफेक में कॉपीराइट सामग्री का अनधिकृत उपयोग शामिल है तो वे कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) डीपफेक की प्रकृति के आधार पर मानहानि (धारा-499) और आपराधिक धमकी (धारा-506) जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। डीपफेक से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों में तकनीकी समाधान सर्वोपरि है। डीपफेक का पता लगाने और प्रमाणित करने के लिए शोधकर्ता एआई-संचालित उपकरण विकसित कर रहे हैं। ये उपकरण डीपफेक सामग्री में सूक्ष्म खामियों का विश्लेषण करते हैं, जैसे चेहरे के भाव या आंखों की गतिविधियों में विसंगतियां। सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन डीपफेक से निपटने के लिए कानूनी और नियामक ढाँचे की खोज कर रहे हैं। इसमें साइबर अपराध के एक रूप के रूप में डीपफेक को परिभाषित करना, रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना और उत्पादकों और वितरकों को जवाबदेह बनाना शामिल है। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा के जरिये डीपफेक के प्रभाव को कम करने के लिए जनता को इसके बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसमें लोगों को डीपफेक की पहचान करना, हेरफेर की क्षमता को पहचानना और ऑनलाइन सामग्री साझा करने के बारे में सतर्क रहना सिखाना शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डीपफेक से निपटने की ज़िम्मेदारी है। इसमें पता लगाने वाली तकनीकों में निवेश करना, स्पष्ट नीतियां लागू करना और कानून प्रवर्तन के साथ काम करना शामिल है। डीपफेक से निपटने के लिए एआई-आधारित समाधान में चेहरे की हरकतों, त्वचा की बनावट और आवाज के पैटर्न में सूक्ष्म विसंगतियों के आधार पर डीपफेक की पहचान करने के लिए एआई मॉडल को प्रशिक्षित किया जा सकता है। सोर्स कोड वॉटरमार्किंग डिजिटल सामग्री के सोर्स कोड में अद्वितीय वॉटरमार्क-एम्बेडेड करने से डीपफेक की उत्पत्ति का पता लगाने और अपराधियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

खास खबर

हवा पकड़े रफ्तार तो प्रदूषण से मिले निजात

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

राजधानीवासियों को अगले कुछ दिन तक प्रदूषण से बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है, अगले तीन दिन तक दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण हवा की बेहद धीमी रफ्तार को माना जा रहा है। शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को प्रदूषण में मामूली कमी देखी गई। शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 था तो शनिवार को यह 355 रिकॉर्ड किया गया।

धूप निकलने से मिली थोड़ी राहत

नवंबर के बाद दिसंबर में भी राजधानी में प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस माह की शुरूआत में ही प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। अगले तीन-चार दिनों तक इसमें राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। शनिवार को दिल्ली में सुबह से देर शाम तक हवा की रफ्तार न के बराबर रही। इसके चलते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कणों का बिखराव नहीं हो सका। स्मॉग की परत भी दिल्ली में शनिवार को बनी रही। सुबह के समय जहां कोहरा रहा तो दिन में धूप निकली। इसके चलते प्रदूषण में मामूली कमी देखने को मिली है।

आज भी राहत मिलने की संभावना नहीं

विशेषज्ञों का मानना है, प्रदूषण कम होने के लिए हवा की गति बढ़ना जरूरी है। लेकिन, अभी हवा की रफ्तार किसी भी दिन 6-7 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा नहीं हो रही। शनिवार सुबह दिल्ली में धुंध छाने से प्रदूषण में हल्की बढ़ोत्तरी देखने को मिली। सुबह के समय दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 रहा। बाद में धूप निकलने के चलते इसमें मामूली कमी आई। रविवार को भी दिल्ली में हवा की गति 4 से 6 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने की संभावना है। इसके चलते रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के आसपास रहने की संभावना है।

सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र शादीपुर रहा

शनिवार को दिल्ली का सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र नेहरू नगर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया। सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र शादीपुर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 255 दर्ज किया गया। दिल्ली में शादीपुर और डीटीयू ही ऐसे इलाके रहे, जहां प्रदूषण खराब श्रेणी में रहा।

छेड़छाड़ के विरोध पर मणिपुरी युवक को अधमरा किया

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

सनलाइट कॉलोनी थानाक्षेत्र के किलोकरी गांव में गुरुवार रात पत्नी और बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर अज्ञात लोगों ने मणिपुर के युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। हमलावरों में एक महिला भी शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि पीड़ित मूलरूप से मणिपुर के निवासी हैं और फिलहाल दिल्ली के आश्रम स्थित जीवन नगर इलाके में रहते हैं। गुरुवार रात करीब 11.30 बजे वह खाना खाने के बाद अपनी पत्नी और बहन के साथ दोस्त को उसके घर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में किलोकरी गांव में उन्हें एक महिला समेत तीन अजनबी लोग मिले। उनसे पीड़ित ने मुनिरका के लिए उबर कैब बुक करने में मदद मांगी, क्योंकि पीड़ित का मोबाइल फोन बंद हो चुका था। आरोप है कि इस दौरान अजनबियों में से एक पीड़ित की पत्नी और बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस पर पीड़ित ने विरोध जताया तो तीनों आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज और बदसुलूकी की। विवाद बढ़ा तो आरोपियों ने कॉल कर अपने कुछ और साथियों को वहां बुला लिया। आरोपियों ने पीड़ित को घेर लिया और पीट-पीटकर उन्हें अधमरा कर दिया। शुक्रवार तड़के 2.30 बजे झगड़े की पीसीआर कॉल पर सनलाइट कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि पीड़ित के घुटनों, आंखों और माथे पर बाईं तरफ काफी चोट आई है।

सनलाइट कॉलोनी थाने में शुक्रवार तड़के 2.30 बजे झगड़े की पीसीआर कॉल मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई की। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज के सहारे आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

दाखिला प्रक्रिया : त्रुटि पर भी अस्वीकार नहीं होगा आवेदन फॉर्म

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा की सामान्य सीटों पर दाखिला आवेदन की प्रक्रिया जारी है। दाखिला पंजीकरण के आवेदन के दौरान त्रुटि होने पर अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है।

आवेदन फॉर्म अस्वीकार नहीं होगा। अभिभावक आवेदन की त्रुटि को दोबारा से ठीक करवा सकेंगे। दरअसल, अलग-अलग स्कूलों में आवेदन में त्रुटि होने के सवालों को लेकर अभिभावक स्कूलों में पहुंच रहे हैं। अभिभावकों के मन में डर है कि त्रुटि के कारण उनका आवेदन अस्वीकार न हो जाए। हालांकि, रोहिणी स्थित माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति अरोड़ा ने कहा, दाखिला पंजीकरण के दौरान आवेदन फॉर्म में कोई गलती होने पर आवेदन अस्वीकार नहीं होगा। अभिभावक उसमें सुधार करवा सकते हैं। लेकिन, उसके लिए स्कूल को पत्र लिखना होगा। हमारा प्रयास होता है कि अभिभावक इन सब चीजों को लेकर ज्यादा परेशान न हों।

फॉर्म अच्छे से पढ़कर ही भरें

मयूर विहार फेज तीन स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. सतवीर शर्मा ने कहा, पंजीकरण में गलती लेकर अभिभावक ज्यादा चिंतित न हों। जब बच्चे का सूची में नाम आ जाता है तो उस समय स्कूल दाखिला फॉर्म अलग से भरवाते हैं। उस समय भी वह त्रुटि ठीक की जा सकती है। दोबारा से भी अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक आवेदन फॉर्म अच्छे से पढ़कर ही भरें।

जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भरे सूचना

आवेदन में सही-सही जानकारी दें। अगर दाखिला पंजीकरण के बाद पते में कोई बदलाव किया जाता है तो उस फॉर्म को पहली सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके लिए दूसरी सूची का इंतजार करना होगा। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में दी गई नाम संबंधी सूचना के आधार पर आवेदन भरें। स्कूलों में दाखिला आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है।

नरेला में जलाशयों के पुनर्निर्माण की मांग

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

नरेला में कई जलाशय सूखे पड़े हैं। स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए ने इन जलाशयों को फिर से विकसित करने की मांग की है। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के अनुसार, नरेला में 50 से अधिक जलाशय हैं, जिनका पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। स्थानीय सुशील कुमार ने बताया कि 20 से 25 वर्षों में नरेला के जलाशय सूख चुके हैं। इनके पुनर्निर्माण की जरूरत है।

फिलहाल नरेला में कई प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, मगर उससे पहले नरेला और आसपास की सड़कों तथा पुराने फ्लैटों के रखरखाव के लिए बेहतर कदम उठाए जाएं। एक माह में दो से अधिक बार सामुदायिक भवन में अधिकारी लोगों के साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर बैठक करें। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नरेला में निर्माण से जुड़े सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। स्थानीय मुद्दे हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

आईजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से कई फ्लाइट डायवर्ट, यात्री हुए परेशान

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

सर्दी में मौसम में कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी का असर राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। इसके कारण आज कई फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट्स को दिल्ली की बजाय अहमदाबाद, जयपुर और अमृतसर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट डायवर्ट होने से हवाई यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें अकेले विस्तारा एयरलाइंस की पांच फ्लाइट डायवर्ट हुई हैं। फ्लाइट संख्या यूके 906 जो अहमदाबाद से दिल्ली आ रही थी। उसे वापस अहमदाबाद ही डायवर्ट किया गया। इसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट संख्या यूके 26 जो फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही थी, उसे अमृतसर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। उस एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लगभग 11 बजे के आसपास लैंड करवाया गया। फ्लाइट संख्या यूके 832 जो चेन्नई से दिल्ली आ रही थी, उसे भी अमृतसर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट संख्या यूके 954, जो मुंबई से दिल्ली आ रही थी, उसे जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। सुबह 8:42 के आसपास फिर उस फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी ठीक होने के बाद दोबारा जयपुर से ही दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा फ्लाइट संख्या यूके 928, जो मुंबई से दिल्ली आ रही थी, उसे भी जयपुर एयरपोर्ट पर ही डायवर्ट किया गया। इसकी लैंडिंग सुबह 09.45 पर करवाई गई। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे कोहरा बढ़ेगा वैसे-वैसे आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होगी और डायवर्ट होने वाले फ्लाइट की संख्या और भी बढ़ सकती है।

दिल्ली दंगा: शरजील इमाम की वैधानिक जमानत पर फैसला 9 दिसंबर को

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने वैधानिक जमानत याचिका पर 9 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान आज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपको लगता है कि हम फ्री हैं। हर तारीख पर यही होता है। वकील नहीं आते। हम मामले को टालते रहें। कोर्ट ने डीसीपी क्राइम के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्या आपके लिए ये केस महत्वपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने 13 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 29 अगस्त को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। शरजील इमाम की ओर से वकील अहमद इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने याचिका में कहा है कि उसने अधिकतम 7 साल की सजा की आधी सजा काट ली है। ऐसे में उसको तत्काल जेल से रिहा किया जाए। याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है। वैधानिक जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपराध की गंभीरता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि सिर्फ इसलिए कि आरोपित ने उसके ऊपर दर्ज मामलों में मिलने वाली अधिकतम सजा का आधा हिस्सा जेल में बिता लिया है। इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में जंतर-मंतर पर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली

भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना का बिहार और यूपी के युवाओं ने विरोध किया। युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने चंपारण सत्याग्रह नाम के बैनर तले इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि वह पिछले 3 वर्षों से इस संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ निराशा हाथ लगी है।

बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय सेवा में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना का विरोध काफी समय से रहा है, लेकिन अभी तक इस योजना को वापस नहीं लिया गया है। आज जंतर मंतर पर बिहार से पहुंचे युवाओं ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना युवाओं के हित के लिए नहीं है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और सिर्फ 4 वर्षों के लिए हमें नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अग्निपथ योजना से पहले उन लोगों का सेवा में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन नौकरी नहीं दी गई। इसके पीछे कारण बताया गया कि नई प्रक्रिया के तहत अब लोगों की भर्ती होगी। अब केंद्र सरकार से अपना हक मांगने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं।वहीं, उत्तर प्रदेश के आगरा से पहुंचे सुभाष का कहना है कि 2021 में आर्मी का फिजिकल मेडिकल पास कर लिया था।

उनका वेरिफिकेशन भी हुआ था। सारी चीज पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने सारी भर्तियां रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि कई बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई अमल नहीं हुआ है। जंतर मंतर पर पहुंचे युवाओं का कहना है कि हम वही युवा है जो इस सरकार को देश में सत्ता के अंदर लेकर आए थे। लेकिन आज सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार की जो अग्निवीर योजना इस योजना से पहले ही हम लोग आर्मी के लिए क्वालीफाई कर चुके थे।

ईडी ने आंध्र-तेलंगाना में मछली टैंकों के निर्माण से जुड़े मामले में की कार्रवाई

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मछली टैंकों के निर्माण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की मंजूरी में धोखाधड़ी के संबंध में जांच के लिए आंध प्रदेश और तेलंगाना में छह जगहों पर तलाशी ली। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह तलाशी अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)- 2002 के प्रावधानों के तहत चलाया है। ईडी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि मछली टैंकों के निर्माण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण की मंजूरी में धोखाधड़ी के मामले में जांच के लिए छह स्थानों पर तलाशी ली गई। यह तलाशी अभियान 29 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऋण एग्रीगेटर्स के छह आवासों और कार्यालय परिसरों में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत चलाया गया था। ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान में डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही इस तलाशी अभियान के दौरान आय से अर्जित कई चल-अचल संपत्तियों का खुलासा करने वाले दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

दिल्ली में 10 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिसंबर

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

दिल्ली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा 10 दिसंबर को दिल्ली के सभी कोर्ट में कुल मिलाकर 300 से ज्याद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित की जाएगी। यह इस साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसलिए लोगों के पास इस साल में अपने मामलों का निस्तारण करने का यह अंतिम मौका ही है। इसके बाद अगले साल में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लोगों को दो से तीन महीने इंतजार करना पड़ेगा। डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। छह दिसंबर को डाउनलोड करें चालानः इसके अलावा अपने यातायात चालानों का निस्तारण कराने के लिए लोग छह दिसंबर को सुबह 10 बजे से चालान डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद लोक अदालत के आयोजन के दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं। इस बार लोक अदालत में एक लाख 77 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है। इन सभी के निपटारे के लिए सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 177 बेंच लगाई जाएगी। दो करोड़ से अधिक चालान लंबितः बता दें कि आठ अक्टूबर को आयोजित हुई तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल एक लाख 78 हजार

848 मामलों का निस्तारण हुआ था। साथ ही 791.35 करोड़ रुपये का जुमार्ना वसूला गया था। वहीं, एक लाख से ज्यादा ट्रैफिक चालान का निस्तारण हुआ था। साथ ही एक करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित हैं। इस तरह कराएं यातायात चालान का निस्तारणः लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को छह दिसंबर को सुबह 10 बजे ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा।

तब जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल : आतिशी

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किए गए "मैं भी केजरीवाल" हस्ताक्षर अभियान के तहत कैंपेन के तहत शनिवार को 'आप' की वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री आतिशी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कालकाजी विधानसभा में डोर टू दूर कैंपेन किया। उन्होंने गोविन्दपुरी, कालकाजी में घर-घर जाकर लोगों से पूछा कि अगर झूठे केस के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। उधर, विधायक ऋतुराज झा ने किराड़ी, विधायक प्रमिला टोकस ने आरके पुरम और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र तोमर ने त्रिनगर में डोर-टू-डोर कैंपेन कर जनता की राय जानी। सभी जगह जनता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो जाए, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री,

विधायक, नेता डोर टू डोर कैंपेन के लिए ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। हम दिल्ली की जनता की राय लेने के लिए निकले है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार और भाजपा झूठे आरोप लगा-लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। भाजपा ने सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ़्तार करा लिया और अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ़्तार करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उधर, आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष ऋतुराज झा ने किराड़ी विधानसभा, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र तोमर ने त्रिनगर और विधायक प्रमिला टोकस ने आरके पुरम विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन किया। ऋतुराज झा ने कहा कि हमारे सभी मंत्री, विधायक, पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक-एक घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं।

डायनासोर थीम पार्क दिसंबर अंत तक शुरू होगा

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

दिल्ली में कचरे से कला की थीम पर आधारित नया पार्क शुरू होगा। दिल्ली नगर निगम ने सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क के दूसरे चरण में डायनासोर थीम पर पार्क बनाया है। पार्क में कई प्रजातियों के डायनासोर को प्रदर्शित किया गया। इसे दिसंबर अंत तक शुरू करने की योजना है।निगम अधिकारियों के अनुसार, पार्क का 80 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है, शेष कार्य दो सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। पार्क का दूसरा चरण 3.50 एकड़ में विकसित किया गया है। डायनासोर थीम पार्क की निर्माण लागत 13.72 करोड़ रुपये होगी। इसमें 300 टन कबाड़ का उपयोग किया गया है। आठ कलाकार और 60 से अधिक कर्मचारियों ने इसे तैयार किया है। इसमें लोहे, टायर और खंभे समेत कई तरह के कबाड़ का इस्तेमाल हुआ है। यहां लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी, जिनमें खानपान के लिए रेस्तरां और बैठने की व्यवस्था भी शामिल होगी।

टिकट पर पुनर्विचार करने की हुई मांग

कई आरडब्ल्यूए ने इस थीम पार्क की टिकट दर पर पुनर्विचार करने की मांग की है। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के अनुसार, अगस्त में आईटीओ स्थित शहीदी पार्क में नए थीम पार्क और आउटडोर संग्रहालय को शुरू किया गया था। इसका टिकट 100 रुपये है। इसे कम किया जाना चाहिए। इस पार्क में एक माह में एक हजार से अधिक लोग पहुंच रहे हैं, जबकि यह संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए। टिकट के दाम कम होने से पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क और पंजाबी बाग स्थित भारत दर्शन पार्क के आसपास वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

डीयू : 53 कॉलेजों में बनेंगे भारत की उपलब्धियों के सेल्फी प्वाइंट

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरंधर टाइम्स

जेएनयू, जामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 कॉलेजों समेत अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के कैंपस में भारत की उपलब्धियों को दशार्ते सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे। इसमें अंतरिक्षक्कयात्रा, खेल उत्कृष्टता, बुनियादी ढांचे व महिला नेतृत्व वाले विकास, सतत ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल कनेक्टिविटी समेत कई अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों को दशार्ते सेल्फी प्वाइंट बनेंगे। इसका मकसद छात्रों को भारत की इन उपलब्धियों के बारे में जागरूक करवाना है। खास बात है कि शिक्षा क्षेत्र में एनईपी 2020, एक भारत-श्रेष्ठ भारत, हैकाथॉन, आईआईटी दिल्ली और मद्रास के विदेश में स्थापित होने वाले कैंपस मुख्य हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छात्रों को भारत की उपलब्धियों की जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 कॉलेजों के प्रबंधन को इन विषयों के सेल्फी प्वाइंट बनाने के लिए पत्र लिखा गया है। ताकि छात्र सेल्फी के माध्यम से इन उपलब्धियों के बारे में जान सकें। संस्थान केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए 3डी लेआउट में अनुमोदित डिजाइन के अनुसार सेल्फी पॉइंट लगा सकते हैं। ये सेल्फी पॉइंट न केवल गर्व के स्रोत के रूप में काम करेंगे, बल्कि प्रत्येक नागरिक को उन परिवर्तनकारी पहलों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के विकास को बढ़ावा दिया है। छात्रों और आगंतुकों को इन विशेष क्षणों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैद करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सेल्फी पॉइंट की थीम में एक भारत : श्रेष्ठ भारत जैसी राष्ट्रीय पहल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के प्रमुख क्षेत्रों का व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। यूजीसी का मानना है कि इन संस्थानों में सेल्फी पॉइंट राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने के लिए एक गतिशील और आकर्षक स्थान के रूप में उभरेंगे और युवाओं में जागरूकता पैदा होगी और भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी।

3 डी लेआउट वाले डिजाइन : सेल्फी प्वाइंट 3 डी लेआउट डिजाइन वाले होंगे। सेल्फी प्वाइंट को थीम के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें एक ओर पीएम नरेंद्र मोदी का कटऑउट भी होगा। दरअसल, युवाओं में सेल्फी विद पीएम का सबसे अधिक क्रेज रहता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय से लेकर अन्य सेल्फी प्वाइंट में भी युवा पीएम के साथ वाली सेल्फी लेना पसंद करते हैं। जेएनयू, जामिया, बीएचयू भी शामिल : यह सेल्फी प्वाइंट डीयू के अलावा जेएनयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया,बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समेत अन्य विश्वविद्यालय में भी बनाए जाएंगे। कैंपस में एक जगह निर्धारित करके यह सेल्फी प्वाइंट बनेंगे।

बिजली बिल के नाम पर बैंक खातों से की जा रही है साइबर ठगी

जमुई । लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। बावजूद इसके पढ़े-लिखे लोग भी साइबर फ्रॉड में फंस कर ठगे जा रहे हैं। जमुई में फिर एक बार साइबर फ्रॉड हुआ है। जहां बिजली विभाग का एसडीओ बनकर साइबर ठग ने एक महिला के बैंक खाते से करीब 7 लाख रुपए गायब कर दिये। ठगी की शिकार महिला व्यवसाई ने जमुई साइबर थाना में आवेदन दे कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। साइबर ठग ने इसके बैंक के खाते से एनी डेस्क ऐप्प से 6 लाख 88 हजार रुपये उड़ा लिये हैं। जमुई जिले के साइबर थाने में आवेदन देने वाली महिला गुलाबी कुमारी ने बताया है कि उसके पति अरुण कुमार तांती के मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर दूसरे तरफ से एक शख्स ने बोला कि हम बिजली विभाग का एसडीओ बोल रहे हैं आपका बिजली बिल अपडेट नहीं है, हम आपकी बिजली काट रहे हैं। फिर वह शख्स बोला कि 10 रुपया का रिचार्ज कर दो तो बिजली बिल अपडेट हो जाएगा। फिर उस शख्स ने सुविधा एप से 10 रुपये का रिचार्ज कराया और एक लिंक भेज कर झांसे में लेते हुए एनीडेस्क ऐप्प का कोड डाउनलोड कर 10 अंकों का कोड उसके पति से ले लिया। उसके बाद महिला के दो बैंक खातों से 6 लाख 88 हजार रुपये की राशि निकाल ली। कुछ देर बाद दूसरे नंबर से एक और कॉल आया। वह संबंधित व्यक्ति भी फ्रॉड में शामिल था। इस मामले में साइबर थाने के इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई की जा रही है।

तीन राज्यों में जीते कई सांसदों व मंत्रियों की लोकसभा सदस्यता खत्म होने का खतरा

नई दिल्ली। तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में शानदार जीतने के बाद भले ही भाजपा ने सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन भाजपा के सामने उस मामले में फैसला लेने की चुनौती भी है जिसमें कई सांसद चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। भाजपा द्वारा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए दिग्गजों को चुनाव में उतारा गया था। इनमें 21 सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं। जिनमें 12 सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनाव जीत गए हैं। यह मुद्दा भाजपा के गले की फांस बन गया है क्योंकि इन चुने विधायकों को 14 दिन में तय करना है कि उन्हे दोनों में से कौन-सा पद रखना है। वर्ना उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा 5 सांसद मध्य प्रदेश से जीते हैं, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 4 और छत्तीसगढ़ में 3 है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। अब इन सांसदों से इस्तीफा लिया जाता है तो उनकी खाली हुई सीटों पर नए चेहरों की तलाश करनी होगी। इस दौर में यदि भाजपा दिग्गजों को केंद्रीय राजनीति में रखने के लिए 3 राज्यों में नए चुने किसी विधायक से इस्तीफा लेगी तो उस सीट पर विधानसभा उपचुनाव करवाना होगा। भाजपा द्वारा जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव लडने् के लिए मैदान में उतारा गया था उनमें केंद्रीय मंत्रि भी हैं। जिनमें से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रफुल्ल पटेल, रेणुका सिंह को जीत हासिल हुई है जबकि फगन सिंह कुलस्ते हार गए हैं।

अरब सागर में 40 मछुआरों वाली नाव लापता, तलाश शुरू

बेंगलुरु । अरब सागर में 40 मछुआरों को ले जा रही एक मछली पकड़ने वाली नाव लापता हो गई है। यह घटना राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार की है। सूत्रों के अनुसार, नाव पिछले सप्ताह कर्नाटक के अधिकार क्षेत्र में अरब सागर में मौसम की विपरीत स्थिति के बीच लापता हो गई थी। गोवा में पंजीकृत क्रिस्टोरी नाम की नाव के इंजन में तकनीकी समस्याओं का सामना करने और तेज हवाओं के कारण नाव के बह जाने का संदेह है। सूत्रों के मुताबिक, यह गोवा के पणजी से रवाना हुआ था और आखिरी जीपीएस सिग्नल उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में बेलिकेरी के पास रिकॉर्ड किया गया था। चार दिन तक सिग्नल नहीं मिलने के बाद तटीय गार्डों ने लापता नाव का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया है।

ईवीएम पर सवाल उठाना जनता के जनादेश का अपमान : मेघवाल

नई दिल्ली । 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद देश में ईवीएम पर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, वहीं जवाब में भाजपा उन्हें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की जीत की याद दिला रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा की जीत पर सवाल उठाकर ईवीएम से वोटिंग पर सवाल उठाया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विपक्ष को नकारात्मकता छोड़नी चाहिए, लेकिन विपक्ष ऐसा करने को तैयार नहीं है। मेघवाल ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि जब वह कर्नाटक में जीते थे, हिमाचल प्रदेश में जीते थे, तब क्या उस समय ईवीएम से वोटिंग नहीं हुई थी क्या ? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तमाम तथ्यों की जांच करने के बाद, परीक्षण करने के बाद ईवीएम को लेकर सारे तथ्य सामने रख चुका है। इसके बाद भी शिकायत बार-बार करना सही नहीं है। अगर कांग्रेस को कोई शिकायत है, तब उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनावी नतीजे पर सवाल उठाना एक तरह से मतदाताओं का अपमान है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर कहा कि जब वह हिमाचल और कर्नाटक में जीते तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, इस बार भी वे तेलंगाना में चुनाव जीते हैं लेकिन वहां भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष कर कहा कि विपक्ष को न तो जनता पर विश्वास है और न ही चुनाव पर विश्वास है और इस तरह से जनादेश को अस्वीकार करना उनकी बहुत ही छोटी सोच है।

कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के चुनाव आयोग रिश ?वतखोरी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को रद्द करने की मांग करने वाली कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और अभियोजन शिकायत को रद्द करने की मांग कर रहा है। उसने ट्रायल कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि वह उसके समक्ष लंबित आपराधिक मामले को आगे न बढ़ाए। जैसा कि ईडी ने तर्क दिया कि चंद्रशेखर की एक समान याचिका पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है, चंद्रशेखर के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछली याचिका में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यदि उसे विधेय अपराध में बरी कर दिया गया हो या यदि मामला रद्द कर दिया गया हो। इसमें आरोप लगाया गया है कि ईडी की जांच और मुकदमे की कार्यवाही कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसका उद्देश्य परेशान करना और पूर्वाग्रह पैदा करना है। चंद्रशेखर पर तमिलनाडु में उपचुनाव के लिए पार्टी का चुनाव चिह्न दो पत्तियां सुरक्षित करवाने के लिए पूर्व अन्नाद्रमुक नेता टी.टी.वी. दिनाकरन से धन लेने का आरोप है।

50 से ज्यादा कंपनियों के कफ़ सिरप के सैंपल, टेस्ट में फेल

नई दिल्ली । देश में इन दोनों दवा निर्माता कंपनियों द्वारा अमानक दवाइयां बनाकर महंगे दामों पर बेची जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त संख्या में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। दुकानों से सैंपल इकट्ठे नहीं किया जा रहे हैं। जिसके कारण दवा निर्माता कंपनियां भारी लूट मचाते हुए आम आदमियों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा कफ सिरप के 54 कंपनियों से 2104 नमूने परीक्षण के लिए एकत्रित किए गए थे। 54 कंपनियों में से मात्र चार कंपनियों के कफ सिरप मानक पर खतरे खरे उतरे हैं। जबकि 50 कंपनियों के कफ सिरप अमानक पाए गए हैं। गुजरात की औषधि एवं खाद्य प्रयोगशाला के 385 मुंबई की सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेट्री में 523 चंडीगढ़ प्रयोगशाला में 284 गाजियाबाद के भारतीय फार्माकोपोयिया आयोग ने 502 नमूनो का विश्लेषण किया। इसमें 50 कंपनियों के कफ सिरप पूरी तरीके से अमानक पाए गए हैं। उल्लेखनीय है जीसीआई ने जांच प्राथमिकता के आधार पर करने के आदेश दिए थे। रिपोर्ट भी जल्दी देने के आदेश किए गए थे। उल्लेखनीय है कि गुजरात के खेड़ा जिले में कफ सिरप के पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। दो लोग बीमार हो गए थे। उसके बाद व्यापक स्तर पर इसकी जांच कराई गई। जिसमें 50 कंपनियों के कफ सिरप पूरी तरीके से अमानक पाए गए। पिछले वर्ष भारतीय कंपनियों के कफ सिरप से उज्बेकिस्तान में 89 बच्चों की मौत हुई थी। तभी मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था।

गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश ने बढ़ाई टेंशन, भारत पहुंचा अमेरिका जांच दल

नई दिल्ली (एजेंसी)। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश मामले में भारत पर लगे आरोपों को लेकर मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में अमेरिका लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या कहें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली आए हैं। पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश मामले में भारत पर लगे आरोपों पर भी बात करने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है।

व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री के साथ मुलाकात की। फाइनर ने महत्वाकांक्षी यूएस-इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 4 दिसंबर को

बयान में आगे कहा गया, फाइनर ने अमेरिका में हत्या की साजिश को लेकर भारत के जरिए जांच समिति की स्थापना की जानकारी ली। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार व्यक्ति को जवाबदेह ठहराने के

महत्व को स्वीकार भी किया।

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहता है। उसके पास कनाडा और अमेरिका दोनों की नागरिकता है। अमेरिका में भले ही लोग उसे सामाजिक कार्यकर्ता और वकील के तौर पर जानते हैं। मगर वह वहां से बैठे-बैठे ही भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा रहता है। पन्नू सिख फॉर जस्टिस (एसजेएफ) नाम के खालिस्तानी संगठन का प्रमुख भी है। पन्नू और उसके संगठन दोनों पर भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है।

दरअसल, पिछले हफ्ते अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 52 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के ऊपर पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में शामिल होने के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया। जस्टिस डिपार्टमें की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, भारत सरकार के एक सरकारी कर्मचारी ने निखिल गुप्ता के अलावा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमेरिका की धरती पर न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले भारतीय मूल एक अटॉर्नी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हत्या की कोशिश की।

मोदी सरकार की पहल, केवल लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना मथुरा के संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम

नई दिल्ली । भारत में जल्दी ही इसतरह के सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है, जो केवल लड़कियों के लिए होगा। अभी तक देश में कोई सैनिक स्कूल ऐसा नहीं है, जो केवल लड़कियों के लिए बनाया गया हैं। हालांकि देश में को-एजुकेशन वाले सैनिक स्कूल मौजूद हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ते हैं। हालांकि अब पीपीपी मॉडल के तहत शुरू किए जा रहे सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से स्कूल शुरू किया जा सकता है। रक्षा राज्य मंत्री के मुताबिक, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मथुरा में संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी दी गई। इस बारे में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया कि पूर्ववर्ती पद्धति के तहत देश में 33 सैनिक स्कूल स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अमेठी, झांसी और मैनपुरी में स्थापित किए गए तीन सैनिक स्कूल भी शामिल हैं। भट्ट ने बताया कि ये सभी स्कूल सहशिक्षा वाले हैं। पूर्ववर्ती पद्धति के तहत केवल लड़कियों के लिए ही सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी व राज्य सरकार के स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने की पहल के तहत केवल लड़कियों के लिए ही सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। रक्षा राज्य मंत्री के मुताबिक, इस संबंध में, मथुरा में संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी दी गई है।

मध्य प्रदेश में भाजपा को नहीं मिल रहा शिवराज का विकल्प, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम की तलाश

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। तीनों ही राज्यों में कई दिग्गज नेता हैं जो वर्षों से मुख्यमंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के लिए मुख्यमंत्री तय करना चुनौती बन गया है। किसे खुश करें और किसे नाराज, बस इसी उलझन को सुलझाने लिए राज्यों की राजधानियों से लेकर देश की राजधानी तक विचार मंथन शुरु हो गया है। राज्यों के कई नेताओं ने दिल्ली में ढेरा डाल दिया है तो कुछ अपनी बयानबाजी से भाजपा हाईकमान को खुश करने के प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में गोमती साय और राजस्थान में किसी बाबा को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है।

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य की कमान सौंपने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। वजह ये है कि मुख्यमंत्री चौहान अपनी लोकप्रियता और सभी स्वीकार नेता के रुप में पहचान बना चुके है। उनकी योजनाओं ने आम लोगों को प्रभावित किया है। इसके अलावा चौहान की जमीनी पकड़ भी फिलहाल कम नहीं हुई है। उन्होंने 120 लोगों को टिकट दिलाए थे जिसमें से 89 विधायक जिताकर लाए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां प्रमुख रुप से गोमती साय का नाम सीएम की रेस में लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष अरुण कुमार साव, निवर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व आईएएस

अधिकारी ओपी चौधरी को भी मुख्यमंत्री पद का संभावित दावेदार माना जा रहा है। सिंह को छोड़कर बाकी तीनों नेता अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं। हालांकि, यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में अपने फैसले से पहले भी कई बार हैरान कर चुका है। इसी तरह राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम आ रहे हैं। यहां कुछ बाबाओं को सपने में सीएम की कुर्सी दिखाई दे रही है। कोई मीट की दुकाने बंद कराने के निर्देश दे रहा है तो कोई गुंडे बदमाशों बंगाल और कर्नाटक भेजने की सलाह दे रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने की होड़ में इन आचार्य बालमुकुंद और बाबा बालकनाथ का नाम चर्चा में है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है। जबकि ओम माथुर, ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का भी नाम चर्चा में है।

बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आए. जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 160 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं कांग्रेस पार्टी महज 65 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं 25 नवंबर को राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित किया गया। इस दौरान बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की. जबकि कांग्रेस केवल 69 सीटों पर रह गई।

बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के नीचे बनने जा रही है देश की पहली सुरंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। बुलेट ट्रेन के लिए देश की पहली समुद्र के नीचे सुरंग बनने वाली है। जिसके निर्माण का काम शुरू करने का समय तय हो गया है। यह सुरंग 21 किमी लंबी होगी। सबसे अहम बात यह है कि सात किमी सुरंग समुद्र के नीचे बनेगी, जिसका निर्माण मुंबई में होगा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का काम अब रफ्तार पकड़ने वाला है। बताया जा रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होगी। यहां पर पूरा स्टेशन और ट्रैक दोनों भूमिगत होंगे। यहां से सुरंग बनेगी जो समुद्र के नीचे से होकर जाएगी। इस सुरंग का निर्माण अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि यह सुरंग सात किमी समुद्र के नीचे से गुजरेगी। रेलवे मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले काम चालू हो जाएगा। संभावना है कि मार्च 2024 से सुरंग के लिए खुदाई शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर पहले ही दिए जा चुके हैं। गौरतलब है कि देश में पहली बार समुद्र के नीचे सुरंग बनने जा रही है। अभी तक इस तरह की टनल बोरिंग मशीन नहीं है, अब अलग-अलग देशों से टीबीएम के पाट्र्स मंगाए जा रहे हैं और यहीं पर असेंबल किए जाएंगे। इसके बाद खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। मंत्रालय के अनुसार दो से तीन माह में टीबीएम असेंबल हो

जाएगी।

बता दें कि यह सुरंग बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स भूमिगत स्टेशन और शिलफाटा के बीच होगी। इस समय देश में तमाम शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो चल रहीं हैं, इसके लिए भी सुरंग बनाई गयी थीं, लेकिन कोई सुरंग पानी के नीचे नहीं बनी है। हालांकि कोलकाता में हुबली के नीचे सुरंग है लेकिन वह केवल 520 मीटर लंबी है। समुद्र के नीचे इस तरह का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए यह सुरंग मेट्रो से अलग है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सुरंग निर्माण में टनल बोरिंग मशीन और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। विदेशों में यह तकनीक सफल है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किमी लम्बी भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण कर रहा है, जिसका 352 किमी मार्ग गुजरात के नौ और महाराष्ट्र के तीन जिलों से होकर गुजरेगा।

अब शुरू हुई लोकसभा चुनाव में 186 सीटों पर भाजपा को टक्कर देने की चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के सामने असल चुनौती तो अब शुरू हुई हैं। जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस भले ही विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की गतिविधियों को आगे बढ़ाकर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा कर दे, लेकिन उसके सामने असल चुनौती भाजपा के खिलाफ खुद लड़ने की है। पिछले दो चुनावों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो कांग्रेस भाजपा के साथ सीधे मुकाबले वाली सीटों पर हारी है। पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के मध्य 186 लोकसभा सीटों पर सीधा मुकाबला था और कांग्रेस इसमें से महज 15 सीटें ही जीत पाई थी। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले वाली सीटों में से 162 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को महज 24 सीटें हासिल हुई थी। 2014 के बाद 2019 के चुनाव में भाजपा के साथ सीधे मुकाबले वाली सीटों पर कांग्रेस की जीत का प्रतिशत कम हो गया था और उसने अपनी 9 सीटें गंवा दी थीं।

कांग्रेस 2023 में हिमाचल और कर्नाटका विधानसभा चुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित है। उसने इन विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके बावजूद असली चुनौती लोकसभा चुनाव की है, जहां उसे पिछले दो लोकसभा चुनावों में हुई अपनी हार का विश्लेषण करते हुए नए तरीके से रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। कांग्रेस भाजपा के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड के अलावा कर्नाटका व महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर सीधे मुकाबले में होगी और पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन सारे राज्यों में कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया था। अब कांग्रेस यदि अपनी सीटें न बचा पाई तो लोकसभा में उसकी स्थिति पहले वाली ही रह सकती है।

मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने पीएम से पूछा सवाल, शांति बहाली के लिए क्यों नहीं की पहल

नई दिल्ली (एजेंसी)। मणिपुर की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को पीएम मोदी से सवाल किया है। कांग्रेस ने पूछा कि अभी तक केन्द्र ने शांति बहाली के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। कांग्रेस ने मांग की है कि नरेन्द्र मोदी को अपनी 'चुप्पी तोड़ते हुए बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि पूर्वोत्तर के इस राज्य में एक ऐसा समाधान निकल सके जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह सवाल किया कि केंद्र सरकार ने राज्य में शांति बहाली के लिए अब तक कोई प्रत्यक्ष कदम क्यों नहीं उठाया? गौरतलब है किल मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में सोमवार को उग्रवादियों के दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम 13 लोग मारे गए। राज्य में सात महीने पहले शुरू हुए अशांति के दौर में

अब तक 180 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कांग्रेस नेता खरगे ने 'एक्स पर पोस्ट किया, 'मणिपुर में सात महीने तक हिंसा जारी रहना अक्षम्य है। कथित गोलीबारी में 13 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले 215 दिनों में 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। राहत शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे हैं जहां स्थिति अमानवीय और संतुष्टि से दूर है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने का जिम्मेदार कौन है?

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी पूछा कि सीएम एन बीरेन सिंह के पद पर बने रहने के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार द्वारा गठित शांति समिति ने मणिपुर में शांति, सामान्य स्थिति और सद्भाव बहाल करने के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य क्यों नहीं किया है?

उन्होंने कहा कि मणिपुर में कई राजनीतिक दलों के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी ने मांग की है और फिर से दोहराया है कि केवल माननीय प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा से ही संघर्ष का कोई ऐसा समाधान निकल सकता है जो सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो। हमें पूरी उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स पर लिखा कि अब 7 महीने हो चुके हैं। मणिपुर में हालात सामान्य से काफी दूर हैं। कल ही हिंसा का एक ताजा दौर शुरू होने की खबर आई जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि राज्य में शांति लौट आई है लेकिन जमीनी हकीकत इसके हटकर है।

केसीआर के अतिआत्मविश्वास ने तेलंगाना में डूबो दी सरकार

हैदराबाद (एजेंसी)। ऐसा लगाता है कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेतृत्व सत्ता विरोधी लहर को समझने में विफल रहा और लगभग सभी मौजूदा विधायकों को दुबारा टिकट दिया गया। इससे पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि लगभग एक दशक तक देश के सबसे युवा राज्य पर शासन करने के बाद बीआरएस को कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कुछ वर्गों में बीआरएस नेतृत्व के अहंकारी होने की सार्वजनिक धारणा और भ्रष्टाचार के आरोप भी पार्टी की बुरी तरह से हार के लिए जिम्मेदार अन्य कारक थे। पार्टी नेतृत्व का चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और इतना ही नहीं एग्जिट पोल को भी स्वीकार करने से इनकार करना दर्शाता है, कि वह अपनी संभावनाओं को लेकर अति आत्मविश्वास में थी।

चूंकि 119 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के कुल 104 विधायक थे, इसकारण केसीआर को लगाता था कि भले ही पार्टी कथित सत्ता विरोधी लहर के कारण 40 सीटें हार जाए, फिर भी वह सत्ता रहेगी। जैसा कि बाद में पता चला, पार्टी को 65 सीटों का भारी नुकसान हुआ, लगभग उतनी ही सीटें जितनी कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए जीती हैं। टीआरएस (अब बीआरएस) ने 2014 में 63 सीटें जीतकर सत्ता की अपनी यात्रा शुरू की थी। यह एक नया राज्य था और वहां तेलंगाना की प्रबल भावना थी। केसीआर ने लगभग छह दशकों तक संयुक्त आंध्र प्रदेश में हुए भेदभाव के बाद राज्य को पुनर्निर्माण के पथ पर ले जाने का वादा किया था। उन्होंने स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और अन्य दलों के विधायकों को लालच दिया। केसीआर ने अपनी सरकार के प्रदर्शन पर नए जनादेश की मांग कर 2018 में समय पूर्व चुनाव कराने का जुआ खेला। वापसी के प्रति आश्वस्त होकर, उन्होंने अधिकांश मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से बहुत पहले उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। केसीआर का दांव काम कर गया और पार्टी ने 88 सीटों के भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। चुनाव के बाद, केसीआर ने मुख्य विपक्षी दल का लगभग सफाया करने के लिए कांग्रेस के एक दर्जन विधायकों को लालच दिया। अन्य दलों के चार और विधायक भी बीआरएस में शामिल हो गए, जिससे इसकी संख्या 104 हो गई।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, विधायक खरीदना भी लोगों के गले नहीं उतरा। हालांकि इस बार केसीआर ने समय से पहले चुनाव नहीं कराया, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने से लगभग ढाई महीने पहले 21 अगस्त को 115 उम्मीदवारों की घोषणा की। सात बदलावों को छोड़कर, उन्होंने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया। लंबे अंतराल ने कांग्रेस को असंतुष्ट बीआरएस नेताओं को अपने गुट में लाने का समय भी दे दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी.रामा राव ने पार्टी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का हवाला देकर दावा किया था कि पार्टी को 2018 में हासिल की गई सीटों से अधिक सीटें मिलेंगी। अपने ही कर्मचारियों के एक वर्ग की संलिप्तता से तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के लीक होने, बार-बार परीक्षाओं को स्थगित करने और यहां तक कि रद्द करने के कारण नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को होने वाली समस्याओं और कुछ कथित आत्महत्याओं को लेकर बेरोजगार युवाओं में गुस्सा है। इन कारकों ने बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को केसीआर सरकार के खिलाफ कर दिया।

राजनीतिक विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा कि कुछ लोग मनाते हैं कि भाजपा और बीआरएस के बीच एक मौन सहमति थी। इस विचार को तब बल मिला जब केंद्र की भाजपा सरकार कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में केसीआर की बेटी के. कविता के प्रति नरम रुख अपनाती दिखी। भगवा पार्टी के नेताओं ने पहले यह प्रचार किया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कई आलोचकों ने भाजपा पर केसीआर की चुप्पी पर सवाल उठाए, जबकि कुछ महीने पहले वह भगवा पार्टी पर पूरी तरह हमला बोल रहे थे। वह भाजपा द्वारा बीआरएस विधायकों को तोड़ने के कथित प्रयास पर भी चुप हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर में एक भाजपा नेता के तीन कथित एजेंटों को रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद केसीआर ने भाजपा द्वारा उनकी सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया था, जब वे बीआरएस के चार विधायकों को भारी धन की पेशकश के साथ लुभाने की कोशिश कर रहे थे।

स्वामी मुद्रक, प्रकाशक व संपादक धुरन्धर चौहान द्वारा मूलनिवासी प्रिंटिंग प्रेस, मकान नं. 21 व 22, ब्लॉक, आर-3/ए-3, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-110059 से मुद्रित तथा कार्यालय 'धुरन्धर टाइम्स' डी-405, ब्लॉक-डी मंगोलपुरी, नई दिल्ली-110083 से प्रकाशित किया। किसी भी कानूनी वाद-विवाद की स्थिति में दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगा। RNI : DELHIN/2016/71837 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं। विवादास्पद केवल दिल्ली में होंगे।